Eastern States and beyond. We would like to know whether the Government is aware of this and the intentions of the Chinese and, if so, what action is being taken to prevent such a serious happening. This august House would like to have all information about this serious matter.

Thank you very much.

Non-payment of statutory dues like Gratuity and Provident Fund to sick public sector units like Jessop, M.M.A.C., N.T.C. etc. involving thousands of workers

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I am happy that mr. Mulayam Singh Yadav is also present in the House. This is an issue which I have been raising since I came to this House - right from April 1994. This is about non-payment of statutory liability post-retirement benefits to the workers of a socalled sick Central public sector undertaking.

मैंने इसको शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन के हिसाब से 24.9.95 को इसी हाउस में रखा था। कहा गया था कि कुछ करेंगे। फिर 16.7.96 को इसके ऊपर मैंने जीरो आवर में सबमिशन किया था। हजारों रिप्रेजेंटेशन हो गए हैं और इसी सत्र में सेकेंड दिसम्बर को हमारी नयी गवर्नमेंट के, नयी सरकार के मिनिस्टर बोलते हैं - वे मानते हैं कि 2,294 workers of the Jessop Company have not been getting their gratuity since 1993.

तीन साल से ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। सरकारी कंपनियों में काम करने वाले लोग रिटायर हो गए हैं। क्यों? वे सिक हैं। इसी तरह की और दस कंपनीज हैं एन. टी.सी., एम.एम.टी.सी. वगैरह-वगैरह। दस हजार इंप्लायीज हैं। यहां इतना डिसकशन होता है, अंग्रेजी में हिंदी में हमको पता नहीं चलता कि इनकी सुनने वाला कोई है या नहीं। कब तक ये डिसकशन करेंगे? स्पेशल मेंशन, जीरो आवर करेंगे? आज मुलायम सिंह यादव जी नये मंत्री, नयी गवर्नमेंट के, नयी सरकार के हैं। मैं यादव जी से अपील करता हूं कि ये खाली बंगाल में काम करने वाले नहीं हैं। ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हैं। रिटायर करके चले गए हैं। सरकारी कारखानों से ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है।

In reply to Unstarred Question No. 1016 dated 2nd December 1996, the Labour Minister, Mr. Arunachalam, himself has admitted that "non-payment of gratuity is a punishable offence."
whether the MPs are getting their retirement

मैं किसको सजा दूं? पिछली सरकार को? उसमें तो कोई है नहीं। इस सरकार को समय दे दिया है 6-7 महीने का। यादव जी हैं और चतुरानन जी चले गए हैं। मैं क्या सोचूं इसके बारे में। क्या आप लोग इसके बारे में सोचेंगे कि ग्रेच्युटी उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद मिले इसके लिए कितनी बार यहां चिल्लाना पड़ेगा। I want to know benefits or not. If they can get this benefit, why not these people? Is it because the company is being called a sick Central public sector unit that they do not get their pension, gratuity and provident fund?

मैं पूछना चाहता हूं यहां के सांसदों से। जो लोग यहां से रिटायर करके गए हैं उनको पैंशन मिल रही है या नहीं? उनको पैंशन देने के लिए अगर सरकार को पैसा मिलता है, मंत्रियों को पैसा मिल सकता है तो बेचारे 2294 "जैसप" कंपनी के मजदूरों को ग्रेच्युटी का क्यों नहीं मिल सकता? मैं यादव जी से प्रार्थना करूंगा कि इस इश्यू को आप कैबिनेट में ले जाएं। यही कहकर आई थैंक्यू वेरी मच। Thank you very much.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): महोदय श्री दीपांकर मुखर्जी के इस सवाल से मैं अपने को संबंध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि जो सेवानिवृत कर्मचारी हैं उनके ग्रेच्युटी और प्राविडेंट फंड के जो पैसे हैं उनको समयबद्ध रूप से दे दिया जाए। वे सरकारी क्षेत्र के हैं। उनको भूखों न मारा जाए। उनको परेशान नहीं किया जाए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर अविलम्ब कार्यवाही करके उनको भुगतान करें। इतना कहकर मैं इसका समर्थन करता हूं।

†[شری جلال الدین انصاری (بہار): مہودے-
شری دیپانکر مکرجی کے اس سوال سے میں
اپنے کو سمبدھ کرتا ہوں اور سرکار سے
مانگ کرتا ہوں کہ جو سیوانورت کرمچاری
ہیں - انکے گریجویٹی اور فنڈ کے پیسے
ہیں انکو سمبندھ روپ سے دے دیا جائے
وہ سرکاری شیتر کے ہیں - انکو بھوکوں نہ
مارا جائے - ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس بار
ادیلمب کارروائی کرکے انکو بھگتان کرے -
اتنا کہکر میں اسکا سمرتھن کرتا ہوں - "ختم شد"]

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं भी इसके साथ अपने को जोड़ना चाहूंगा। जब निजी क्षेत्र में ऐसे कोई कर्मचारी होते हैं तो ऐसे प्रबंधकों को निश्चित तौर पर सजा मिलती है।

2.00 P.M.

लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा होगा तब तो फिर कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र तो ऐसा होना चाहिए कि वह देश के लिए एक उदाहरण बने। लेकिन वह स्थिति बन नहीं पा रही है। कृपा करके मुझे भी इसके साथ जोड़ना है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA): It is 2.00 p.m. now. Members have to seek clarifications on the statement made by Shri Mulayam Singh Yadav regarding procurement of SU-30 MK aircraft. These names are with me. I will read out the names.

Shri John Fernandes. Not present.

Dr. Y. Radhakrishna Murty.

† [ ] Transliteration in Arabic script.

[The Vice-Chairman (Shri Triloki Nath Chaturvedi) *in the Chair]*

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

Procurement of SU-30 MK Aircraft

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY (Andhra Pradesh): Sir, on behalf of my party, I support the agreement for the purchase of the SU-30 MK aircraft on three counts. One is the. need for augmenting our air-defence system, which is long due. It is said that for the last ten years there was almost a drought in acquisition of defence aircraft. It is also said that our combat aircraft are ageing and probably they may have to retire within ten years. Pakistan is acquiring the most modern aircraft, the so-called P3C Orion maritime reconnaisance plane under the Brown Agreement with Harpoon missiles.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I am sorry. I hate to intervene, but I have to remind the hon. colleague that the hon. Minister has to leave at 2.30 p.m. and we have to finish this. So, it will be better if you will confine yourself to pointed questions for seeking clarifications. This is my only submission to you.

DR. Y. RADHAKRISHNA MURTY: The agreement is an indication of the enduring friendship which we are having with Russia even though the Governments have changed qualitatively. The super power has been almost pressurising us directly or indirectly to stall our defence preparedness. This is evident in the case of our Agni missile, in the case of the cryogenic rocket technology transfer to us, in the case of our purchase of Mirage 2000 deal with France etc. In all these cases it is the U.S. pressure that is stalling the help to us from other countries for our defence preparedness.

I want to know from the Defence Minister whether we are going to have deals with similar